

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति प्रेस कॉन्फ्रेंस का संपादित प्रतिलेख: 07 दिसंबर, 2022

आरबीआई से प्रतिभागी:

श्री शक्तिकांत दास - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री एम. के. जैन - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

डॉ. माइकल डी. पात्रा - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री टी. रबी शंकर - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

डॉ. ओ. पी. मल्ल - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री सौरभ सिन्हा - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री आर. सुब्रमण्यम - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

डॉ. राजीव रंजन - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

संचालक: श्री योगेश दयाल - मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

योगेश दयाल:

नमस्कार और नीति घोषित होने के बाद कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ गवर्नर श्री शक्तिकांत दास; उप गवर्नर श्री एम. के. जैन, डॉ. माइकल डी. पात्रा, श्री टी. रबी शंकर; और कार्यपालक निदेशक डॉ. ओ. पी. मल्ल, श्री सौरभ सिन्हा, श्री आर. सुब्रमण्यम और डॉ. राजीव रंजन, साथ ही मौद्रिक नीति विभाग से मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। आज हमारे साथ मीडिया से 21 सहयोगी जुड़े हैं। इससे पहले कि मैं उन्हें सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करूँ, मैं गवर्नर महोदय से अनुरोध करूँगा कि कृपया वे कुछ शुरुआती संबोधन दें, ताकि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर सकें।

शक्तिकांत दास:

धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आप सभी को यहाँ देखकर खुशी हुई।

इस बार के वक्तव्य में, एक खास पैराग्राफ 15 है, जिसमें मैंने मुख्य बातों को संक्षेप में बताने की कोशिश की है। फिर भी, मैं आज की मौद्रिक नीति की मुख्य बातों के तौर पर छह बिंदुओं पर रोशनी डालना चाहूँगा।

पहला, भारत की जीडीपी वृद्धि मज़बूत है। यह टिकी हुई है और ऐसे समय में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जब दुनिया भर में कई देशों में वृद्धि धीमी हो रही है और मंदी की आशंकाएँ बनी हुई हैं।

दूसरा, प्रमुख महंगाई कम हो रही है। मैं यह कहना चाहूँगा कि महंगाई का सबसे बुरा दौर अब बीत चुका है। इस बात पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए - महंगाई का सबसे बुरा दौर अब बीत चुका है। वैश्विक स्तर पर भी यही रुझान देखने को मिल रहा है, जहाँ वस्तुओं की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें और कई अन्य कीमतें कम हो रही हैं।

तीसरा, जहाँ एक ओर महंगाई कम हो रही है—और हम यह मानते और कहते भी हैं कि महंगाई का सबसे बुरा दौर अब बीत चुका है—फिर भी, हमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। हमें बेहद सतर्क रहना होगा और यदि ज़रूरत पड़ी, तो हमें अपनी कार्रवाई में तेज़ी दिखानी होगी। इसलिए, महंगाई के खिलाफ़ यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि महंगाई का सबसे बुरा दौर अब बीत चुका है और यह धीरे-धीरे कम हो रही है; हमने अगले साल की दूसरी तिमाही तक महंगाई के संभावित रुझान के बारे में जानकारी दे दी है।

चौथी बात, मैं चलनिधि के बारे में कहना चाहूँगा। हम चलनिधि डालने के लिए चलनिधि परिचालन करने को तैयार हैं, लेकिन हम चलनिधि चक्र में बदलाव के पक्के संकेतों का इंतज़ार करेंगे।

पाँचवीं बात, भारतीय रुपये की कहानी मज़बूती और स्थिरता की कहानी है। हम अपनी विनिमय दर में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए कदम उठाने को पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा ध्यान विनिमय दर के व्यवस्थित विकास पर ही बना रहेगा।

छठी बात, चालू खाता घाटा पूरी तरह से संभालने लायक है, और इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। इसे और विस्तार से समझाएँ तो, विदेशी मुद्रा भंडार 21 अक्टूबर को 524.5 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2 दिसंबर, 2022 को 561.2 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है; यह 36.7 बिलियन अमेरिकी डालर की बढ़ोतरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भारत का बाहरी कर्ज़ अनुपात कम है।

मैं कहूँगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कुल स्थिति काफी मज़बूत है। मुझे लगता है कि एक अस्थिर और निराशाजनक दुनिया में भारत एक मज़बूत द्वीप की तरह उभरकर सामने आया है। धन्यवाद।

योगेश दयाल:

सर, आपके प्रारंभिक संबोधन के लिए धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने के लिए, मैं 'बिजनेस टुडे' से श्री आनंद अधिकारी को अपना सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

आनंद अधिकारी, बिजनेस टुडे:

नमस्कार, सर। मैं बस मौजूदा मौद्रिक सख्ती के दौर में आरबीआई की 'टर्मिनल रेट' के बारे में जानना चाहता हूँ; क्या आरबीआई के पास फेड की 'टर्मिनल रेट' का कोई अनुमान है? क्या इस बारे में कोई अंदाज़ा है?

शक्तिकांत दास:

सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा, वह यह है कि फेड दर या टर्मिनल दर पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कई पहलुओं पर असर डालती है—खासकर करेंसी मार्केट के संबंध में। हमारी नीतियाँ मुख्य रूप से हमारे घरेलू कारकों—यानी विकास और महंगाई के घरेलू परिदृश्य—द्वारा संचालित और निर्धारित होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम फेड की नीति दर को देखकर अपना फ़ैसला लेते हैं। हम अपनी मौद्रिक नीति दर के रुख पर फ़ैसले अपने घरेलू कारकों के आधार पर लेते हैं।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं इकॉनॉमिक टाइम्स के श्री गोवर्धन रंगन की ओर रुख करूँगा।

एम. गोवर्धन रंगन, इकॉनॉमिक टाइम्स:

नमस्कार गवर्नर सर। आपने महंगाई के बारे में बात की, कि सबसे बुरा दौर अब पीछे छूट गया है, लेकिन साथ ही आपने यह भी कहा कि हम इस बारे में लापरवाह नहीं हो सकते। सुबह की बातचीत में अपने भाषण में, आपने कहा था कि यह डेटा पर निर्भर करेगा। तो, अगर इन तीनों बातों को एक साथ देखें - अगर डेटा उस रास्ते से नहीं भटकता है जिसका आपने अनुमान लगाया है; तो क्या इसका मतलब यह होगा कि आप ब्याज दर के चरम चक्र के करीब पहुँच रहे हैं?

शक्तिकांत दास:

हम एक अनिश्चित दुनिया में जी रहे हैं। भविष्य का परिदृश्य बेहद अनिश्चित है। इसलिए, अगर हालात हमारी उम्मीदों से मेल नहीं खाते हैं, तो हम क्या करेंगे - इस बारे में इस स्तर पर मेरे लिए कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। हम बस इतना कह रहे हैं कि हम समग्र नज़रिया पर लगातार नज़र रखेंगे और जब भी ज़रूरी होगा, हम कदम उठाएँगे। पिछले लगभग तीन

सालों में, जब भी ज़रूरत पड़ी, हमने हर तरह से - न सिर्फ़ ब्याज दरों के मामले में - बल्कि हर पहलू में, सक्रियता और असरदार तरीके से कदम उठाए हैं। जब हमने ब्याज दरें कम की थीं, तो हमारी कोशिश थी कि हम जितना हो सके, उतनी तेज़ी से कदम उठाएँ। अब, जब हम मई से ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, तो हम आने वाले डेटा और भविष्य के परिदृश्य से ही निर्देशित हो रहे हैं।

इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे और यह किस ओर इशारा करता है, यह पूरी तरह से आपकी अपनी व्याख्या होगी। मेरे लिए यह कहना संभव नहीं है कि इसका मतलब यह है या फिर वह। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, लेकिन कृपया यह समझें कि हम अपने घरेलू कारकों को ही आधार बनाएंगे, और हम आने वाले डेटा पर नज़र रखेंगे, क्योंकि हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। हम भविष्य के परिदृश्यों के साथ-साथ महंगाई और विकास की उभरती और बदलती गतिशीलता का भी लगातार आकलन करते रहेंगे, और उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं सीएनबीसी- टीवी18 की सुश्री लता वेंकटेश की ओर रुख करूंगा।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी18:

गवर्नर साहब, मौजूदा रेपो रेट 6.25% के आधार पर, एक साल बाद के लिए आपका महंगाई का अनुमान 5.2% है। अगर आप अगले साल की पहली और दूसरी तिमाही का औसत लें। तो, आपकी पूर्व निर्धारित वास्तविक दर 100 आधार अंक है। जब आपने तटस्थ से निभावकरण की ओर रुख किया था, तब यह 2% थी।

शक्तिकांत दास:

85 आधार अंक; सही हिसाब 85 आधार अंक; ही होगा।

लता वैकटेश, सीएनबीसी-टीवी18

जी। तो, क्या आप उस तरह की 'वास्तविक दर' चाहते हैं? आपके मन में क्या है? क्योंकि आपने पिछली नीति में भी इसका उल्लेख किया था।

शक्तिकांत दास:

हम इस पर आंतरिक तौर पर काफी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। मैं उप गवर्नर डॉ. माइकल पात्रा से अनुरोध करूँगा कि वे इस सवाल का जवाब दें।

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

जैसा कि आपने गवर्नर साहब से सुना, 'वास्तविक दर' अभी सिर्फ 85 बीपीएस है। यह स्तर सिर्फ दूसरी तिमाही में ही हासिल हो जाएगा। उस समय, महंगाई का अंतर कितना होगा? क्या महंगाई अपने तय लक्ष्य पर होगी? यही वह सवाल है जिस पर हमें विचार करना होगा।

लता वैकटेश, सीएनबीसी- टीवी18

अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए आपने एक नया शब्द इस्तेमाल किया है—'कोर इन्फ्लेशन' (मूल महंगाई)। आपने कहा कि एमपीसी महंगाई में होने वाली क्रमिक वृद्धियों पर नज़र रखेगी और 'कोर इन्फ्लेशन' के लगातार बने रहने के क्रम को तोड़ेगी। तो, क्या आपके पास इसके लिए कोई निर्धारित मार्ग है? क्या आप चाहते हैं कि वह मार्ग भी सबके सामने आए?

शक्तिकांत दास:

'कोर इन्फ्लेशन' के बारे में हम पहली बार बात नहीं कर रहे हैं। हमने पहले भी इस पर चर्चा की है। पिछले छह-सात महीनों से, यह लगभग 6% के स्तर पर स्थिर बनी हुई है—और यही बात मैंने कही है। इस बार मैंने बस इतना किया है कि मैंने इस मुद्दे को चर्चा के लिए सबके सामने रखा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि जब हम महंगाई से जुड़े अपने विश्लेषण को अलग-अलग

हिस्सों में बाँटकर उसका अध्ययन करते हैं, तो उस समय इस पहलू पर भी विशेष रूप से ध्यान देना और इसे ज़हन में रखना ज़रूरी है।

योगेश दयाल:

धन्यवाद। अब मैं जी बिज़नेस न्यूज़ के श्री ब्रजेश कुमार को आमंत्रित करता हूँ।

ब्रजेश कुमार, जी बिज़नेस न्यूज़:

मेरा सवाल केवायसी से जुड़ा है। अगर कोई ग्राहक खाता खोलना चाहता है, तो बैंक कहता है कि वे खाता ऑनलाइन खोल देंगे। तो, अगर आप बैंक खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं, और केवायसी सत्यापन बैंक ब्रांच जाए बिना हो जाता है, तो केवायसी के नवीकरण के समय हमें शाखा जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसके अलावा, अगर आपकी केवायसी एक बैंक में हो गई है, तो क्या कोई ऐसी केंद्रीकृत प्रणाली है जिससे आपको अलग-अलग बैंकों के लिए अलग से केवायसी न करनी पड़े?

शक्तिकांत दास:

पुनः-केवायसी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको शाखा में जाना ज़रूरी नहीं है। कार्यपालक निदेशक सौरभ सिन्हा आपको इसके बारे में समझाएँगे।

सौरभ सिन्हा:

धन्यवाद, गवर्नर साहब। जैसा कि गवर्नर साहब ने बताया, अगर आप अपना पुनः-केवायसी करवा रहे हैं, तो आपको बैंक की ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी केवायसी डिटेल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो आप बस एक ईमेल भेज सकते हैं या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बैंक को एक मैसेज भेज सकते हैं, और आपका पुनः-केवायसी हो जाएगा। अगर सिर्फ़ आपके पते में बदलाव हुआ है, तो इसी प्रोसेस से आप अपना नया पता बैंक को

भेज सकते हैं, और बैंक उस नए पते को सत्यापित करेगा। यह सत्यापन दो महीनों के अंदर हो जाएगा। बैंक यह काम नए पते पर एक चिट्ठी वगैरह भेजकर करेगा।

आपके दूसरे सवाल के बारे में बात करें तो, अगर किसी एक बैंक ने आपका केवायसी कर लिया है, तो क्या आपको किसी दूसरे बैंक के लिए फिर से केवायसी करवाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। एक सेंट्रल केवायसी रजिस्ट्री (सीकेवायसीआर) है। सीकेवायसीआर में, आपको एक आइडेंटिफायर नंबर दिया जाता है। अगर आप अपना यह पहचान नंबर दूसरे बैंकों के साथ शेयर करते हैं, तो आपको किसी दूसरे बैंक में केवायसी दस्तावेज दोबारा जमा करने की ज़रूरत नहीं है।

ब्रजेश कुमार:

सर, हमें यह फ़ीडबैक मिला है कि बैंक हमें फ़ोन करके कहता है कि आपको शाखा में आना होगा, हम केवायसी सिर्फ़ बैंक में ही करेंगे।

सौरव सिन्हा:

इसके लिए, लोकपाल कार्यालय है। इसके अलावा भी कई ऐसे चैनल हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसी दिक्कतें जानकारी की कमी और जागरूकता की कमी की वजह से पैदा होती हों। आप इस बात को बैंक के ध्यान में ला सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप हमारे विधि से इतर तीव्र समाधान मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।

शक्तिकांत दास:

इस मामले में हमारे नियम-कानून बहुत साफ़ और पारदर्शी हैं। जैसा कि आपने कहा, हो सकता है कि कुछ शाखाओं में ऐसा होता हो। इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है। हमें लोकपाल के ज़रिए शिकायतें मिलती रहती हैं। लोकपाल हस्तक्षेप करके उन मामलों को सुलझाता है। हो

सकता है कि यह सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से हो, और इसके लिए ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। हम आंतरिक तौर पर सभी बैंकों को इन निर्देशों को दोहराते रहते हैं, और जिन बैंकों के खिलाफ हमें ज़्यादा शिकायतें मिलती हैं, उनके साथ हम अनुवर्तन करते हैं।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'बिजनेस स्टैंडर्ड' से श्री मनोजित साहा की ओर रुख करूँगा।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:

नमस्कार, सर। मेरे दो सवाल हैं, अगर आप कृपया अनुमति दें। पहला, आपको क्या लगता है कि मूल मुद्रास्फीति कब नीचे आएगी? आपने आज अपने बयान में कोर इन्फ्लेशन का कई बार जिक्र किया और बाज़ारों ने उस पर प्रतिक्रिया भी दी है। दूसरा सवाल यह है कि एमपीसी के कुछ सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं आपका विचार जानना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि एमपीसी को ब्याज दर तय करते समय विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव पर भी विचार करना चाहिए?

शक्तिकांत दास:

एमपीसी किन बातों पर विचार करती है और एमपीसी की चर्चा में किन पहलुओं को शामिल किया जाता है, इसके लिए आपको बैठक के कार्यवृत्त का इंतज़ार करना होगा। यह ठीक आज से दो हफ़्ते बाद प्रकाशित किया जाएगा। इसलिए, आपको उसके लिए इंतज़ार करना होगा।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:

मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि एमपीसी को ब्याज दर तय करते समय विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव पर विचार करना चाहिए? क्या यह एक विचारणीय बिंदु है?

शक्तिकांत दास:

में यह स्पष्ट कर दूँ कि मुख्य विचारणीय बिंदु हैं—विकास और मुद्रास्फीति, और वे प्रावधान जो कानून में दिए गए हैं। मौद्रिक नीति का उद्देश्य कुछ और है। यह पूंजी प्रवाह के लिए नहीं है। यह विनिमय दर के प्रबंधन के लिए भी नहीं है। विनिमय दर के प्रबंधन के मामले में, हमारा मुख्य ध्यान अस्थिरता को रोकने और पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने पर होता है। अगर आप इसी ओर इशारा कर रहे हैं, तो इसके लिए अन्य साधन मौजूद हैं जिनका उपयोग किया जाना चाहिए। हमने उनमें से कुछ का उपयोग किया भी है। हमने इस वर्ष 6 जुलाई को कुछ घोषणाएँ भी की थीं। इसलिए, मौद्रिक नीति का मुख्य ध्यान घरेलू मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता पर ही केंद्रित रहना चाहिए।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:

क्या आप मूल मुद्रास्फीति का उपयोग कर सकते हैं?

शक्तिकांत दास:

हमारा लक्ष्य हेडलाइन महंगाई दर है। हम हेडलाइन महंगाई दर का विश्लेषण करते हैं और बेशक, इसके एक हिस्से के तौर पर दूसरे पहलुओं जैसे खाद्य महंगाई, गैर-खाद्य महंगाई, गैर-तेल महंगाई और ईंधन महंगाई—इन सभी चीजों का विश्लेषण किया जाता है। हम कोर, ईंधन या खाद्य महंगाई के भविष्य के आंकड़ों के बारे में अलग से कोई जानकारी नहीं देते। हमारा लक्ष्य सीपीआई हेडलाइन के संदर्भ में तय किया गया है, और इसीलिए हम सिर्फ उसी का अनुमान देते हैं; दूसरे अनुमान हम नहीं देते।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के श्री शशांक दिदमिषे से सवाल पूछने के लिए कहूंगा।

शशांक दिदमिषे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस:

सर, व्यापार के निपटारे को लेकर विदेशी विनियामकों के बीच के मतभेदों को सुलझाने के लिए आरबीआई क्या कदम उठा रहा है? और भारत में विदेशी बैंकों के घरेलू कामकाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है?

शक्तिकांत दास:

उप गवर्नर टी. रबी शंकर इस सवाल का जवाब देंगे।

टी. रबी शंकर:

मेरा मानना है कि आप ईएसएमए से जुड़े उस मुद्दे का उल्लेख कर रहे हैं जिसकी आजकल काफी चर्चा हो रही है। इस बारे में बातचीत अभी भी जारी है। हमें उम्मीद है कि बातचीत के ज़रिए हम किसी न किसी तरह की आपसी समझ तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। जब ऐसी कोई स्थिति आएगी, तो हम देखेंगे कि क्या करना है। अगर किसी तरह की रुकावट की कोई भी गुंजाइश बनती है, तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। हम ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित होंगे।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं पीटीआई के श्री बेन जोस से सवाल पूछने के लिए कहूंगा।

बेन जोस, पीटीआई:

नीति दस्तावेज में भारत को एक 'उज्ज्वल स्थान' (ब्राइट स्पॉट) बताया गया है, और यह भी कहा गया है कि भारत बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्था से अलग हो गया है। एमपीसी की नज़र में यह 'उज्ज्वल स्थान' कितना उज्ज्वल है, और हम कब तक इस तरह से उज्ज्वल बने रह सकते हैं? अलग होने के बारे में कई विश्लेषकों का कहना है कि हम काफी हद तक बाकी दुनिया से अलग हो चुके हैं—हमारे ज़्यादातर बाज़ार बाकी दुनिया से अलग होकर काम कर रहे हैं। आरबीआई इस स्थिति को किस नज़र से देखता है?

शक्तिकांत दास:

'उज्ज्वल स्थान' (ब्राइट स्पॉट) वाला मुहावरा आरबीई का गढ़ा हुआ नहीं है। यह आईएमएफ था जिसने कहा था कि भारत एक 'उज्ज्वल स्थान' है। मैं आईएमएफ की कही बातों का ही जिक्र कर रहा था, यानी उस खास मुहावरे के संदर्भ में। जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत ही उथल-पुथल भरे दौर में भारत स्थिरता का एक द्वीप है। इस बयान को अगर आप ध्यान से पढ़ें, तो मैंने एक जगह यह भी कहा है कि आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में, हम बाकी दुनिया में हो रही घटनाओं से पूरी तरह से अलग-थलग नहीं रह सकते।

कुछ मामलों में, हाँ, ऐसा लगता है कि भारत ने खुद को अलग कर लिया है, लेकिन जब पूरी दुनिया इतनी आपस में जुड़ी हुई है, तो हम पूरी तरह से अलग-थलग नहीं रह सकते। इसलिए, यह कोई 'हाँ या ना' वाला मामला नहीं है। जब हम वैश्विक प्रभावों की बात करते हैं, तो दुनिया भर में हो रही घटनाओं के बीच बहुत गहरा आपसी जुड़ाव होता है। ये वैश्विक प्रभाव भारत समेत सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं पर असर डालते हैं। इसलिए, हम पूरी तरह से अलग-थलग नहीं हुए हैं।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं ब्लूमबर्ग से श्री अनूप रॉय की ओर रुख करूँगा।

अनूप रॉय, ब्लूमबर्ग:

सर, वित्त मंत्री ने कहा है कि अब विकास हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपके आकलन के अनुसार, विकास दर थोड़ी कम हो रही है। मुद्रास्फीति पर आपकी टिप्पणी को बाज़ार ने बहुत 'हाँकिश' (आक्रामक) माना; उन्हें उम्मीद थी कि आप कोई अच्छा संकेत देंगे और इसके बाद दरों में ठहराव आएगा या उनमें कमी की जाएगी, लेकिन आपने कहा कि मुद्रास्फीति के

खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो, इसका विकास पर किस तरह का असर पड़ेगा? और क्या अब विकास आपके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं है?

शक्तिकांत दास:

नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। नीति क्या कहती है? कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं? आरबीआई से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता बनाए रखे। सरकार के लिए, ज़ाहिर है, विकास ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। असल में, अपने बयान के एक पैराग्राफ में मैंने कहा भी है कि हमें विकास पर भी ध्यान देना होगा। मैंने नई तकनीक में हो रहे नवाचारों से पैदा होने वाले निवेश के अवसरों का ज़िक्र किया है। मैंने जलवायु परिवर्तन से जुड़े निवेश के अवसरों के बारे में भी बात की है। पीएलआई भी एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी निवेश आकर्षित करेगा। भारत के पास और अधिक निवेश आकर्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए ये अवसर उपलब्ध हैं। मुद्रास्फीति का प्रबंधन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मुद्रास्फीति का प्रबंधन केवल अपने आप में ही महत्वपूर्ण नहीं है; कीमतों में स्थिरता का पहलू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मध्यम-अवधि के विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यदि मुद्रास्फीति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो निवेशक निवेश करना बंद कर देंगे। इसलिए, आपको मुद्रास्फीति का प्रबंधन करना होगा; विकास के हित में कीमतों में स्थिरता बनाए रखना अनिवार्य है। इन दोनों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है।

अनूप राँय, द ब्लूमबर्ग:

जी 20 बैठकों से आपकी क्या उम्मीदें हैं, और आरबीआई क्या हासिल करने की कोशिश करेगा?

शक्तिकांत दास:

हम जी 20 बैठक के फाइनेंस ट्रैक का हिस्सा हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जी 20 बैठकों में कई ट्रैक होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर दो ट्रैक होते हैं: एक है वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक

गवर्नरों का ट्रैक, जिसे फाइनेंस ट्रैक के नाम से जाना जाता है। दूसरा है शेरपा ट्रैक, जिसमें कई दूसरे पहलुओं को शामिल किया जाता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण वगैरह। आखिर में, जब लीडर्स सभा होती है और विज्ञप्ति जारी किया जाती है, तो ये सभी एक जगह मिलते हैं।

इस स्तर पर यह कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि नतीजा क्या होगा, लेकिन जैसा कि मैंने अपने बयान में कहा था, भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी भूमिका निभाने का यह एक शानदार मौका है। कई देशों को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। वे कई मामलों में भारत से बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वह फिनटेक में इनोवेशन हो, डिजिटल पेमेंट्स हों या कई दूसरे क्षेत्र हों। इसलिए, यह भारत के लिए एक बड़ा मौका है। हम फाइनेंस ट्रैक में होने वाली चर्चाओं में हिस्सा लेंगे। सरकार ने फाइनेंस ट्रैक के लिए एजेंडा पहले ही अलग से तय कर दिया है। इसलिए, हम उन चर्चाओं में हिस्सा लेंगे।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' से श्री मयूर शेटी की ओर बढ़ता हूँ।

मयूर शेटी, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया:

गवर्नर साहब, नीति दर अब लगभग वहीं पहुँच गयी है जहाँ महँगाई है। क्या आपको लगता है कि यह दर अभी एक 'न्यूट्रल' (तटस्थ) स्थिति में है? और क्या अगले साल के लिए महँगाई का अनुमान भी 'टॉलरेंस बैंड' (स्वीकार्य सीमा) के अंदर ही रहेगा? तो, अगर यह टॉलरेंस बैंड के अंदर ही रहता है, तो क्या आप यह कहेंगे कि मौद्रिक नीति का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है?

शक्तिकांत दास:

इस सवाल का जवाब डॉ. पात्रा दे सकते हैं।

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

गवर्नर साहब ने कहा है कि महँगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म होने से कोसों दूर है। इसलिए, जब तक हमें महँगाई में कोई ठोस और टिकाऊ गिरावट नहीं दिख जाती—और जब तक यह टॉलरेंस बैंड के अंदर नहीं आ जाती—तब तक हम पूरी तरह से सतर्क रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जिन बातों को ध्यान में रख रहे हैं, वे सही हैं। हमने नीति दर में बदलाव की सीमा को कम कर दिया है। यह सबसे ज़रूरी बात है, जिसे दुर्भाग्यवश अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा रहा है। यह फैसला बहुत सोच-विचार के बाद लिया गया है। लगातार 50 आधार अंक की बढ़ोतरी के बाद, अब इसमें कुछ नरमी आई है। एक तरह से, यह एक बड़े बदलाव का संकेत है। जैसा कि गवर्नर साहब ने बताया, हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि महँगाई का सबसे बुरा दौर अब बीत चुका है; लेकिन महँगाई में यह नरमी बहुत ही धीमी गति से और असमान तरीके से आएगी। इसलिए, हमें सबसे पहले महँगाई को सख्ती से नियंत्रित करते हुए स्वीकार्य सीमा के अंदर लाना होगा, और उसके बाद उसे अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचाना होगा।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'मिंट' से श्री शयन घोष की ओर बढ़ता हूँ।

शयन घोष, मिंट:

सर, मैं थोड़ा यह समझना चाहता था कि हम सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) को किस तरह से अपनी योजनाओं में शामिल कर रहे हैं? आपने अपनी पिछले भाषण स्पीच में भी इसका ज़िक्र किया था। साथ ही, अगर आप हमें यह बता सकें कि अब तक किस तरह के लेन-देन हुए हैं, तो बहुत अच्छा होगा।

शक्तिकांत दास:

में सीबीडीसी से जुड़े एक अलग सवाल का जवाब दूँगा, क्योंकि बहुत से लोग यह सवाल उठा रहे हैं। इसलिए, मैं पहले इस बारे में स्पष्टीकरण दूँगा और फिर यह ज़िम्मेदारी उप गवर्नर, रबी शंकर को सौंप दूँगा, ताकि वे खास तौर पर आपके सवाल का जवाब दे सकें। कई लोग आरबीआई से, मुझसे और साथ ही अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी यह सवाल पूछ रहे हैं कि असल में यूपीआई और इस सीबीडीसी के बीच क्या फ़र्क है। किसी भी यूपीआई लेन-देन में बैंक की मध्यस्थता शामिल होती है। इसलिए, जब मैं कोई यूपीआई ऐप इस्तेमाल करता हूँ, तो मैसेज मेरे बैंक के पास जाता है, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, पैसे पाने वाले के बैंक अकाउंट में अंतरित हो जाते हैं, और उसे अपने मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज मिल जाता है। तो, इस पूरी प्रक्रिया में बैंक की मध्यस्थता होती है। सीबीडीसी में, ठीक कागज़ी करेंसी की तरह—मान लीजिए आप बैंक जाते हैं और वहाँ से ₹1,000 के कुछ नोट निकालते हैं; आप ₹1,000 निकालते हैं, उन्हें अपने पर्स में रखते हैं, फिर किसी दुकान पर जाते हैं, आपको ₹500 देने होते हैं, तो आप ₹500 निकालकर दे देते हैं। यहाँ भी, आप डिजिटल करेंसी निकालेंगे और उसे अपने वॉलेट में रखेंगे—जो असल में आपका मोबाइल फ़ोन ही होगा—और जब आप किसी दुकान पर या किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान करने जाएँगे, तो वह करेंसी आपके वॉलेट से निकलकर उसके वॉलेट में चली जाएगी। इसमें बैंक के ज़रिए कोई रूटिंग या कोई मध्यस्थता नहीं होती है। मुझे लगा कि इस बात को स्पष्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि यूपीआई और सीबीडीसी के बीच क्या फ़र्क है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो उसका जवाब उप गवर्नर रबी शंकर दे सकते हैं।

टी. रबी शंकर:

गवर्नर साहब ने जो कुछ कहा, मैं उसे थोड़ा और विस्तार से समझाना चाहूँगा: ई-रूपी तो पैसा है, जबकि यूपीआई पैसे के लेन-देन का एक ज़रिया है। इसलिए, आप पैसे के लेन-देन के लिए किसी भी भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं; एक बार जब यह बुनियादी बात आपकी

समझ में आ जाएगी, तो आप इन दोनों के बीच का फ़र्क भी आसानी से समझ जाएँगे। मुख्य बात यह है कि यूपीआई का मतलब है पैसे का एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में जाना - गवर्नर ने यही कहा है। यह नकदी का भुगतान है। यह मुमकिन है कि दो प्राइवेट कंपनियाँ वॉलेट सुविधा दें और उनके बीच पैसे का लेन-देन हो। लेकिन, यह मुमकिन नहीं है। यूपीआई का लेन-देन अनिवार्य रूप से एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच ही होना चाहिए। असल में, ई-रूपी भी एक तरह का पैसा ही है, इसलिए इसके इस्तेमाल के कई और तरीके हो सकते हैं, क्योंकि पैसे के कई अलग-अलग काम होते हैं। यह पैसे के उन सभी कामों को कर सकता है। इसे देखते हुए, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम या फिनटेक सिस्टम इस पर कितना नयापन लाता है, और ई-रूपी को आधार बनाकर किस तरह के भुगतान चैनल खुलते हैं। असल में क्या होगा, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। हम इसका बुनियादी सिस्टम तैयार करेंगे, जिसके बाद निजी क्षेत्र इसमें नए-नए प्रयोग कर सकेगा। अब आपके उस सवाल पर आते हैं जो 'गुमनामी' से जुड़ा है - यह करेंसी की एक बुनियादी खासियत है। कई विकसित देशों में आज भी कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने की एक वजह यह भी है कि लोगों को यह बहुत पसंद है। प्राइवेट, और लोगों को अपनी गुमनामी पसंद होती है। इसलिए, गुमनामी के मकसद से, करेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल करेंसी के मामले में गुमनामी कैसे पक्की की जाए, क्योंकि आम समझ यह है कि कोई भी डिजिटल चीज़ अपना निशान छोड़ जाती है, इसके कई हल हो सकते हैं। हम ज़्यादातर पहले तकनीकी हल पर गौर कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ऐसा करने के लिए तकनीकें मौजूद हैं। इसलिए, हम उनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुमनामी पक्की करने के लिए कानूनी प्रावधान लाना भी मुमकिन है। तो, असल में क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, लेकिन गुमनामी करेंसी की एक बुनियादी खासियत है और हमें ऐसा करना ही होगा, और इस हद तक, यह यूपीआई से फिर से अलग है। धन्यवाद।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी- टीवी18:

क्या कोई कानूनी सुरक्षा मिल रही है? यही असली मुद्दा है। तकनीकी सुरक्षा को हमेशा बेहतर तकनीक से तोड़ा जा सकता है। हमें कानूनी सुरक्षा की ज़रूरत है, वरना, मैं इसका इस्तेमाल क्यों करूँगी?

शक्तिकांत दास:

सीबीडीसी के संबंध में आरबीआई अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, उसमें कहा गया है कि मुद्रा में डिजिटल मुद्रा भी शामिल होगी। यही वह संशोधन है जिसे लाया गया है। इसलिए, हर लिहाज़ से, कानून की नज़र में कोई फ़र्क नहीं है, और कागज़ी मुद्रा और डिजिटल मुद्रा के साथ किए जाने वाले बर्ताव में भी कोई फ़र्क नहीं है। आयकर विभाग ने कैश निकालने और कैश भुगतान के लिए कुछ सीमाएँ तय की हैं। एक तय सीमा से ज़्यादा होने पर, आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना होता है। सीबीडीसी के मामले में भी यही नियम लागू होंगे। क्योंकि दोनों ही करेंसी हैं। तो, बात ऐसी है।

लता वैकटेश, सीएनबीसी- टीवी 18:

एक डर यह भी है कि प्रवर्तन निदेशालय किसी दिन बैंक के पास आएगा और कहेगा कि मुझे बताओ कि यह पैसा किसे अंतरित किया गया था।

शक्तिकांत दास:

चलिए, इस बात को स्पष्ट कर लेते हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को मुद्रा नोटों में भुगतान करते हैं, तो आपकी पहचान गुमनाम रहती है। प्रसंगवश, यहाँ भी आप यह पता नहीं लगा सकते, क्योंकि यह जानकारी बैंक के पास उपलब्ध नहीं होती, इसलिए बैंक को भी इस बारे में पता नहीं होता। यह मेरे मोबाइल से किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में चला जाता है। तो, हमें इस तरह का डर क्यों पैदा करना चाहिए? देश का अपना कानून है और अभी तो शुरुआत ही हुई है। रिटेल सीबीडीसी का की प्रयोगिक परियोजना अभी-अभी शुरू हुई है। थोक रूप से

सीबीडीसी प्रयोग का अनुभव बहुत संतोषजनक रहा है। हमने देखा है कि इसके नतीजे बहुत ही संतोषजनक रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने कुल मिलाकर अच्छा काम किया है। प्रक्रियाएं भी कुल मिलाकर ठीक चली हैं, और बाजार के भागीदार तथा अन्य लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि सरकारी प्रतिभूति लेनदेन करते समय किसी भी तरह की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी तरह की गारंटी की ज़रूरत नहीं है और यह एक तुरंत निपटान है। तो, होलसेल सीबीडीसी पर पहले पायलट से मिला फीडबैक बहुत संतोषजनक रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं और हम उन पर काम कर रहे हैं। अब खुदरा की बात करें, तो यह 1 दिसंबर से ही शुरू हुआ है, आज लगभग एक हफ़्ता हो गया है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और हम उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए कि कोई किसी का पीछा करेगा या कुछ और। मुझे लगता है कि यह पूरी कवायद के साथ नाइंसाफ़ी होगी। धन्यवाद।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं इकॉनॉमिक टाइम्स नाउ से श्री अंकुर मिश्रा की ओर रुख करूँगा।

अंकुर मिश्रा, इकॉनॉमिक टाइम्स नाउ (ET NOW):

सर, आपने कहा है कि महंगाई का सबसे बुरा दौर अब पीछे छूट गया है, और कच्चे तेल जैसे डेटा को पूरी तरह से देखें, तो आपने इसकी कीमत 100 से ज़्यादा मानी थी, जो अब लगभग 80 है। तो, अगर महंगाई का सबसे बुरा दौर पीछे छूट गया है, तो क्या अब तक की गई ब्याज दरों में बढ़ोतरी—यानी ज़्यादातर बढ़ोतरी—भी पीछे छूट गई है?

शक्तिकांत दास:

इसका आकलन करना आपका काम है। डॉ. पात्रा इस सवाल का जवाब दे सकते हैं।

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

जैसा कि मैंने बताया, हमने नितिगत दर में बढ़ोतरी के आकार को कम किया है। यही वह बुनियादी संकेत है जो हम बाज़ार को दे रहे हैं। अगर चीज़ें वैसी ही होती हैं जैसा हमने अनुमान लगाया है, तो लगातार 50 आधार अंक की बढ़ोतरी का दौर अब खत्म हो गया है। लेकिन, हम ब्रेक से पैर नहीं हटा सकते, क्योंकि अगले साल भी महंगाई औसतन 5% से 5.4% के बीच रहने का अनुमान है। इसलिए, हमें इसे एक ऐसे स्तर पर लाना होगा जहाँ यह इसी दायरे में स्थिर रहे, और फिर 4% के स्तर पर पहुँचे। तब तक, हमें पूरी तरह से सतर्क रहना होगा— बस यही बात है।

अंकुर मिश्रा, इकॉनॉमिक टाइम्स नाउ:

एक और सवाल ऋण वृद्धि और जमा वृद्धि के बीच बढ़ते अंतर को लेकर है, जो बैंकों के लिए चिंता का एक विषय रहा है। क्या अब तक बैंकों के साथ इस बारे में कोई बातचीत हुई है? क्या आरबीआई ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किया है?

शक्तिकांत दास:

नहीं, आरबीआई बैंकों को उनकी ब्याज दरों के संबंध में—चाहे वह क्रेडिट (ऋण) पक्ष हो या डिपॉज़िट (जमा) पक्ष—कोई निर्देश नहीं देता है। ऋण वृद्धि और जमा वृद्धि को सही नज़रिए से देखा जाना चाहिए। ऋण वृद्धि एक निचले स्तर पर है, जबकि जमा वृद्धि एक ऊँचे स्तर पर है। यही कारण है कि इन दोनों के बीच इतना अंतर दिखाई देता है; वे एक-दूसरे से काफी अलग नज़र आते हैं। महामारी की पूरी अवधि के दौरान, या यहाँ तक कि पिछले साल, ऋण वृद्धि मुश्किल से ही हुई थी, जो लगभग 5%, 6% या उसके आस-पास थी - बेस कम था - लेकिन महामारी के पहले दो सालों में जमा वृद्धि में तेज़ी आई थी। डिपॉज़िट साइड पर अभी जो कुछ भी हो रहा है, उस ग्रोथ को बेस इफ़ेक्ट के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बैंक अपना आस्ति देयता प्रबंध करते हैं, और अपने फंड की ज़रूरतों के आधार पर, अपने खुद के आस्ति देयता आकलन के आधार पर, वे क्रेडिट पक्ष और डिपॉज़िट पक्ष - दोनों पर ज़रूरी कदम उठाएंगे।

हम बैंकों से मिलते रहते हैं। हाल ही में मेरी बैंक कार्यपालकों के साथ एक मीटिंग हुई थी। इसका ब्याज दर से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि वे अब विनियमन से बाहर हैं। उस मीटिंग का मकसद पूरे बैंकिंग क्षेत्र का जायज़ा लेना था - कि वह अभी किस स्थिति में है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, और क्या संभावित जोखिम हैं। यह मोटे तौर पर पूरे बैंकिंग क्षेत्र का एक आकलन है और यह देखना है कि उसका परिदृश्य कैसा है; साथ ही, हमें बैंकों से भी इस बारे में सुनना होता है। जहां एक तरफ हम अपना आकलन करते रहते हैं, वहीं हम यह भी जानना चाहते हैं कि बैंकों का अपना आकलन क्या है।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं फाइनेंशियल टाइम्स की सुश्री क्लो कोर्निश की ओर रुख करूंगा।

क्लो कोर्निश, फाइनेंशियल टाइम्स:

इएसएमए से जुड़ी उलझनों या मुश्किलों के संबंध में, मैं यह जानना चाह रही थी कि अभी भी किन मुद्दों पर असहमति बनी हुई है, और क्या आरबीआई ने इस मोड़ पर किसी भी बात पर रियायत देने का फैसला किया है?

शक्तिकांत दास:

उप गवर्नर रबी शंकर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं।

टी. रबी शंकर:

पिछले सवाल के जवाब में मैंने जो कुछ कहा था, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारे पास देने के लिए कोई और जानकारी बची है। चर्चा अभी भी जारी है। असहमति का मूल बिंदु अभी भी वही है - कि एक भारतीय संस्था, जो यूरोपियन यूनियन में काम नहीं करती और पूरी तरह से भारत में ही काम करती है, उसे यूरोपियन यूनियन के एक रेगुलेटर के रेगुलेशन के दायरे में लाया जा रहा है। मैंने यहां यूरोपियन यूनियन का जिक्र इसलिए किया, क्योंकि

आपने इसी मामले का हवाला दिया था; लेकिन यह स्थिति जापान जैसे कुछ अन्य देशों पर भी समान रूप से लागू होती है। हमारा उनके साथ एक समझौता है; उन्होंने बस आगे बढ़कर कहा कि उन्होंने एक मूल्यांकन किया है, और वह काफी अच्छा है। यह उसके बराबर है, इसलिए वैसी ही चीजें की जा सकती हैं। हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। इसका विस्तृत विवरण संबंधित टीमों के लिए है। चर्चा करने के लिए, लेकिन एक बार जब हम इस बुनियादी मतभेद के मुद्दे पर किसी तरह के समझौते पर पहुँच जाएँगे, तो मुझे लगता है कि हम बाकी बातों को सुलझा पाएँगे।

क्लो कोर्निश, फाइनेंशियल टाइम्स:

बुनियादी मतभेद का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। वे इस मामले पर आपकी बात मानने को तैयार नहीं हैं।

टी रबी शंकर:

हम इस समय इसी पर चर्चा कर रहे हैं।

शक्तिकांत दास:

मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहूँगा। इस पर चर्चा चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि कोई न कोई हल ज़रूर निकल आएगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आज का भारत पहले जैसा नहीं रहा। मैं यह नहीं बताना चाहता कि कब—10 साल पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले। आज हमारे नियम-कानून बहुत मज़बूत हैं। असल में, हम बासेल ढांचे के तहत सीपीएमआई के सभी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हैं। हम सीपीएमआई के सभी मानकों का पालन करते हैं। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं। हमारा बाजार का बुनियादी ढांचा बहुत मज़बूत है। दूसरी तरफ़ के विनियामकों के लिए भी यह समझना और भारतीय नियमों की विश्वसनीयता और मज़बूती पर भरोसा करना ज़रूरी है। हम उन्हें यही

बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर चर्चा चल रही है और हमें उम्मीद है कि कोई न कोई हल जरूर निकलेगा।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं रॉयटर्स की सुश्री स्वाति भट शेट्टे, रॉयटर्स की ओर रुख करूंगा।

स्वाति भट शेट्टे, रॉयटर्स:

सर, आपने बताया कि मूल मुद्रास्फीति अभी भी स्थिर बनी हुई है; क्या आप कृपया बता सकते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मूल मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है? और क्या इससे यह भी संकेत मिलता है कि मांग की वजह से होने वाली मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है? क्या यही वजह है कि हम लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं? दूसरा, मैं यह समझना चाहती थी कि फॉरवर्ड प्रीमियम गिरकर पिछले दस सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गए हैं; आपको क्या लगता है कि ये प्रीमियम कब तक इसी स्तर पर बने रहेंगे और इसका हाजिर दर पर क्या असर पड़ेगा?

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

अगर सिर्फ मुख्य पहलुओं की बात करें, तो इसमें कई कारक काम कर रहे हैं; उदाहरण के लिए, एक कारक है इनपुट लागत का पास-थ्रू। आपने दूसरी तिमाही के कॉर्पोरेट नतीजे देखे होंगे, और आप देख सकते हैं कि खर्च में बढ़ोतरी, आमदनी में बढ़ोतरी से ज्यादा रही है - इसकी मुख्य वजह इनपुट लागत का पास-थ्रू ही है। इसके अलावा, विनिमय दर का पास-थ्रू भी चल रहा है, जिसकी वजह से आयातित महंगाई का दबाव भी इसमें शामिल हो जाता है। हम यह भी देख रहे हैं कि जो चीजें व्यापार योग्य नहीं हैं - यानी सेवाएँ - वहाँ महंगाई बनी रहती है और इसे काबू करना काफी मुश्किल होता है। अब उन चीजों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गयी हैं। शुरू में, मूल का सामान वाला हिस्सा बढ़ रहा था, अब सेवाएँ बढ़ रही हैं। इसलिए, ये तीन

बार्ते हमें चेतावनी देती हैं कि हमें दूसरे दौर के प्रभावों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे आम हो सकते हैं। वे दूसरी श्रेणियों में भी फैल सकते हैं, और हम इसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को यह भरोसा दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं और हम मूल मुद्रास्फीति को नीचे लाएँगे; यह बात आज जारी किए गए प्रत्याशा सर्वेक्षण में भी साफ़ दिख रही है, जिससे पता चलता है कि लोगों की अपेक्षाओं में काफी कमी आई है।

स्वाति भट शेट्टे, रॉयटर्स:

हाजिर दर के बारे में क्या कहेंगे?

शक्तिकांत दास:

स्पॉट रेट क्या होगा, ज़ाहिर है, मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

स्वाति भट शेट्टे, रॉयटर्स:

सर, लेकिन फॉरवर्ड प्रीमियम पहले एक दशक के सबसे निचले स्तर पर गिर गया था; यह वहाँ कब तक रहेगा? यह

आरबीआई के लिए विनिमय दर प्रबंधन को भी मुश्किल बना देता है।

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

इससे हमें यह पता चलता है कि हाजिर बाजार में नकदी की कमी है, लेकिन अब यह कमी दूर हो रही है, क्योंकि फॉरवर्ड प्रीमियम में आज से सुधार आना शुरू हो गया है; यानी, प्रवाह वापस आ रहा है। विनिमय दर में थोड़ी गिरावट आई थी, जिस पर लोगों ने आने वाले पैसे को रोककर प्रतिक्रिया दी। गवर्नर ने विनिमय दर और बाहरी क्षेत्र के बारे में खास आश्वासन दिए हैं, और अब हम देख रहे हैं कि प्रीमियम बढ़ रहे हैं।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। जैसा कि मैंने बताया था, अब हम कुछ आखिरी सवाल लेंगे। तो, मैं बीक्यू प्राइम के श्री विश्वनाथ नायर को अपना सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

विश्वनाथ नायर, बीक्यू प्राइम:

गवर्नर साहब, मेरे दो सवाल हैं। पहला यह कि एक तरफ़ तो आप इन बढ़ी हुई एचटीएम सीमाओं की तारीख़ आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे बैंकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद मिल रही है; लेकिन दूसरी तरफ़, अपने बयान में आपने कहा है कि आपको अतिरिक्त नकदी से बाहर निकलना चाहिए। यह ऐसा समय भी है जब ऋण वृद्धि में तेज़ी आ रही है और यह एक दशक के सबसे ऊँचे स्तर पर है। मैं यह समझना चाहता हूँ कि आप इन दोनों बयानों को एक साथ कैसे देखते हैं?

शक्तिकांत दास:

कार्यपाल निदेशक, सौरभ सिन्हा, क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे?

सौरव सिन्हा:

दोनों का आपस में कोई लेना-देना नहीं है। तारीख़ बढ़ाने का कारण यह है कि बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकें। क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से, उन्हें अपनी पोजीशन बंद करनी होंगी, इसलिए अब उस तारीख़ को एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि बैंकों के लिए प्रक्रिया आसान हो सके।

विश्वनाथ नायर, बीक्यू प्राइम:

दूसरा सवाल सीबीडीसी पर है। चूंकि आपने इस पर इतना विस्तार से बताया है, इसलिए मैं इस पर बात करना चाहता था। अभी, कोई भी दुकान मालिक मना नहीं कर सकता अगर आप कैश में रुपये में भुगतान करते हैं, कोई भी दुकान मालिक यह नहीं कह सकता कि मैं वह

पैसा नहीं लूंगा। क्या यह सीबीडीसी पर भी लागू होगा? क्या कोई दुकान मालिक यह कह सकता है कि मैं सीबीडीसी में भुगतान नहीं लेना चाहता या अगर भुगतान दिया जाता है तो क्या उन्हें कानूनी तौर पर वह भुगतान लेना ज़रूरी होगा?

शक्तिकांत दास:

अभी, यह सिर्फ एक ट्रायल है और यह बड़ी संख्या में व्यापारियों और ग्राहकों का एक छोटा उपभोक्ता समूह है। ट्रायल सिर्फ उन्हीं तक सीमित है जो एक छोटा उपभोक्ता समूह हैं। आगे चलकर, कई चुनौतियाँ आएंगी। हम उन सभी चुनौतियों से निपटेंगे। इस तरह के सवाल और मुद्दे हमारे सामने आएंगे और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम उनसे निपटेंगे।

योगेश दयाल:

मैं द इंडियन एक्सप्रेस से मिस्टर हितेश व्यास के पास जाता हूँ।

हितेश व्यास, द इंडियन एक्सप्रेस:

सर, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में भारत के जीडीपी अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है, जबकि आरबीआई ने दर 7.0% से घटाकर 6.8% कर दिया है। मैं यह समझना चाहता हूँ कि जीडीपी अनुमान में बदलाव के मामले में दोनों संस्थाओं के बीच राय में अंतर क्यों है।

शक्तिकांत दास:

यह सिर्फ 10 आधार अंक का अंतर है। मुझे नहीं पता कि वे किस आधार पर 6.9% पर पहुंचे हैं, मेरे पास उनका आंतरिक आकलन नहीं है। हमारे आकलन में, हमने यह थोड़ा हल्का समायोजन किया है, खासकर इसलिए क्योंकि निर्यात के बाहरी क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है और हालकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा गया है। यह एक हल्का समायोजन है जिसमें जोखिम बराबर संतुलित हैं और कई संभावना हैं। जब हम कहते हैं कि जोखिम बराबर संतुलित हैं, तो इसका मतलब है कि 6.8% भी बढ़कर 6.9% या 7.0% हो जाएगा। हमारे अभी के आकलन

में, हमने कहा है कि यह 6.8% है। बाहरी क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में, एक बात, जिसका मैंने वक्तव्य में जिक्र किया है, बहुत ज़रूरी है, वह यह है कि मर्चेडाइज निर्यात में पिछले महीने में गिरावट के बाद, सेवाओं का निर्यात बहुत तेज़ी से बढ़ा है - सेवाओं के निर्यात में 29.1% की वृद्धि हुई है। इसलिए, हमने 10 आधार अंक का एक छोटा सा बदलाव किया है।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। मुझे लगता है कि सवाल पूछने के लिए मैं जिस आखिरी व्यक्ति को आमंत्रित करूँगा, वह हैं इनफॉर्मिस्ट मीडिया की सुश्री प्रतिज्ञा वाजपेयी।

प्रतिज्ञा वाजपेयी, इनफॉर्मिस्ट मीडिया:

अगर बॉन्ड मार्केट की प्रतिक्रिया को देखें, तो आपकी 35 आधार अंक की दर वृद्धि 50 बेसिस पॉइंट्स जैसी लगती है। मैं पूछना चाहूँगी कि क्या इस बार 50 आधार अंक की वृद्धि पर विचार भी किया गया था? दूसरी बात, यह देखते हुए कि भारत की वृद्धि मज़बूत है और कमज़ोर वैश्विक माहौल में यह भारत के बाहरी व्यापार संतुलन को और बिगाड़ सकती है, तो इस संदर्भ में, क्या माँग में कटौती आरबीआई के लिए एक विचारणीय विषय है?

शक्तिकांत दास:

मैंने अपने बयान में समझाया था कि चालू खाता घाटा पूरी तरह से प्रबंधनीय है। पहली तिमाही के लिए प्रेषण वृद्धि दर 22.6% थी। विश्व बैंक का कहना है कि हमें इस वर्ष के दौरान 100 बिलियन अमेरिकी डालर मिलेंगे। पहली तिमाही के आँकड़ों के आधार पर, विश्व बैंक 12% वृद्धि का अनुमान लगा रहा है, लेकिन हमारी पहली तिमाही की वृद्धि 22% है। प्रेषण बढ़ रहे हैं। सेवाओं का निर्यात भी मूल रूप से बढ़ा है। ऐसे आँकड़े हैं जो दिखाते हैं कि वैश्विक आईटी खर्च भी बढ़ रहा है, इसलिए यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि स्थिति कैसे विकसित होती है। लेकिन आपका मूल प्रश्न क्या था?

प्रतिज्ञा वाजपेयी, इन्फॉर्मिस्ट मीडिया:

बाहरी व्यापार संतुलन के लिए, क्या माँग में कटौती एक विचारणीय विषय है?

शक्तिकांत दास:

हमने आँकड़े दिए हैं। हम हमेशा वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं। वृद्धि के पहलू को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। डॉ. पात्रा, क्या आप इस पर कुछ और जोड़ना चाहेंगे?

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

क्या आप आयात में कमी का जिक्र कर रही हैं?

प्रतिज्ञा वाजपेयी, इन्फॉर्मिस्ट मीडिया:

मैं शुद्ध निर्यात की दिशा के बारे में बात कर रही हूँ।

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

जब मौद्रिक नीति अपनी ढील वापस ले रही होती है, तो ज़ाहिर है वह कुल मांग को सप्लाई के हिसाब से समायोजित करना चाहती है, और इसका असर आयात समेत सभी संवर्ग पर पड़ता है। लेकिन भारत के आयात का एक स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है। आयात के कई हिस्से ऐसे हैं जो स्वभाव से ही ज़रूरी हैं, जैसे कच्चा तेल; हम उसका उत्पादन नहीं करते। इसलिए, कुछ मध्यस्थ और मशीनरी हैं जिन्हें हमें आयात करना पड़ता है, सिर्फ विकास करने के लिए। यह बात भी ध्यान में रखें कि अगर आप आज की दर से ज़्यादा तेज़ी से विकास करना चाहते हैं, तो आपको 2021-22 की तुलना में थोड़ा ज़्यादा चालू खाता घाटा रखना होगा। 2021-22 में सीएडी जीडीपी का 1.0 प्रतिशत था। अब, अगर आप विकास की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा सीएडी रखना होगा। मांग के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें मौद्रिक नीति आयात के मामले में कम नहीं कर सकती, लेकिन जैसा कि गवर्नर सर ने बताया, हमें चिंता करने की

ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बफ़र्स हैं, और जैसे-जैसे विकास दर बदलती है, चालू खाते का आकार भी बदलता है, जो कि व्यावहारिक है।

प्रतिज्ञा वाजपेयी, इन्फॉर्मिस्ट मीडिया:

इसके अलावा, क्या आपने 50 आधार अंक की सीमा पर भी विचार किया?

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

हम इसके हर पहलू पर विचार करते हैं—50, 25, बिल्कुल भी कार्रवाई न करना, या उससे ज़्यादा कार्रवाई करना—और अंत में, काफ़ी सोच-विचार के बाद, हम कोई एक विकल्प चुनते हैं।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। इसी के साथ, हम इस कैलेंडर वर्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के समापन पर पहुँचते हैं; यह इस साल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आरबीआई के शीर्ष प्रबंधन को यहाँ उपस्थित होने और आपके सभी सवालों के धैर्यपूर्वक जवाब देने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, और निश्चित रूप से, मीडिया के उन सभी साथियों का भी धन्यवाद जिन्होंने यहाँ आने का कष्ट किया। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपको नए साल की अग्रिम शुभकामनाएँ।
धन्यवाद।